निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह
विज्ञान भवन, नई दिल्ली
24 फरवरी, 2005

डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार
का अभिभाषण

महामहिम राष्ट्रपति जी, डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम साहब हमारे सहयोगी मंत्री श्री नरेन्द्र जी एवं श्रीमती पाटिल जी, सचिव श्री दुग्गल जी एवं श्री शंकर जी, राज्यों से आए मंत्रीगण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विदेशी संस्थाओं के अधिकारी, निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता एवं सरजमीन से जुड़े हुए पंचायत प्रतिनिधि, पत्रकार बंधुगण एवं उपस्थित बहनों एवं भाइयों ।

आज का दिन अत्यंत गौरव का दिन है कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण करने के लिए उपस्थित हैं । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने अरवस्थता की स्थिति में भी हमारे निमंत्रण को स्वीकारा है एवं यहां उपस्थित होकर हम सब का उत्साह वर्धन किया है । यह इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण विकास, स्वच्छता कार्यक्रम एवं इससे जुड़े मुद्दे आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं । आपकी उपस्थिति ने न सिर्फ इस हॉल में बैठे लोगों को अनुप्राणित किया है बल्कि हजारों सर जमीन से जुड़े कार्यकर्त्ताओं को भी प्रेरित किया है ।

देश का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बगैर संभव नहीं एवं ग्रामीण विकास तभी पूर्ण होगा जब गरीब जनता को न्यूनतम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं । ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हमारा मंत्रालय

सजग है एवं सतत् प्रयास कर रहा है । ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाएं अहम स्थान रखती हैं । देश में स्वच्छता का आच्छादन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम है । आज भी 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है जिससे विभिन्न बीमारियां तो होती ही हैं साथ में बहुत असुविधाओं का भी सामना करना पडता है खासकर महिलाओं, बीमार एवं वृद्ध व्यक्तियों को । देश में प्रतिवर्ष करीब 4 लाख बच्चे डायरिया के शिकार हो जाते हैं जो बहुत चिंता का विषय है । ग्रामीण क्षेत्रों में इस परिदृश्य को बदलना है । एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध हों एवं खुले में शौच की प्रथा से राष्ट्र मुक्त हो । विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र की हमारी उपलब्धियां फीकी दिखाई पड़ेंगी यदि इस समस्या का हम निपटारा न कर सके तो इस हेतु हमारा मंत्रालय संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रहा है जो अभी देश के 452 जिलों में लागू है एवं जिसकी कुल लागत करीब 4500 करोड़ रुपये है ।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत यह तय किया गया है कि वर्ष 2015 तक स्वच्छता सुविधाओं के बगैर रहने वाले लोगों की संख्या आधी कर दी जाए । हम इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने निर्णय किया है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान को अगले वर्ष तक देश के सारे जिलों में लागू कर दिया जाए ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत (2012) तक देश को खुले में शौच करने की विभिषिका से मुक्त किया जा सके ।

इस कार्य के निष्पादन के लिए जो भी धनराशि की जरूरत होगी वह भारत सरकार उपलब्ध करायेगी । हमने ग्रामीण स्वच्छता के बजट प्रावधानों को जो पिछले वर्ष 165 करोड़ रुपये था इस वर्ष बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया था और अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो रहा है । यह इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार इस मुद्दे को कितनी अहमियत देती है। किसी भी अन्य

क्षेत्र के वित्तीय प्रावधानों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है । हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें एवं पंचायतें यदि मिलकर इस कार्य को करें तो शीघ्र ही सफलता मिलेगी ।

स्कूलों में बच्चों को खासकर छात्राओं को असुविधा न हो इस हेतु हमने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2005-06 तक सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था हो जाए । इस कार्य हेतु भारत सरकार के अन्य विभागों एवं मंत्रालयों से समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है ।

एक स्वच्छ एवं निर्मल भारत का निर्माण तभी संभव है जब सभी वर्गों की भागीदारी हो । ऐसे विशाल अभियान की सफलता जन भागीदारी से ही हो सकती है। जन भागीदारी को बढ़ाने में हमारी पंचायती राज संस्थाओं एवं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का अहम स्थान है एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' की घोषणा 2 अक्तूबर 2003 को की गई थी । स्वच्छता एवं स्थानीय निकायों की स्वायत्तता दोनों ही गांधी जी को काफी प्रिय थे इसलिए उनके जन्म दिवस पर उनकी प्रेरणा से इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी ।

अनेक दौरों के मूल्यांकन के बाद 40 पंचायती राज संस्थाओं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है जो आज महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करेंगे । यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे हम प्रतिवर्ष फरवरी महीने में प्रदान करने की कोशिश करेंगे । इस हेतु प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनका मूल्यांकन कर अगले वर्ष फरवरी महीने में एक राष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार वितरण किया जायेगा ।

इस वर्ष तो सिर्फ 8 राज्यों-तमिलनाड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात एवं केरल की पंचायतें यह पुरस्कार पा रही हैं मगर हमें पूरा विश्वास है कि

अगले वर्ष तक देश के प्रत्येक राज्य की पंचायतें अच्छा कार्य करेंगी एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करेंगी।

स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के लिए आवश्यक है लोगों को जागरूक करना । जन जागरण के विभिन्न तरीके हैं एवं पेयजल आपूर्ति विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक संचार नीति तैयार की है । इस संचार नीति के तहत टी.वी., रेडियो, अखबार, व्यक्तिगत संपर्क इत्यादि माध्यमों से स्वच्छता के संदेशों को पहुंचाया जाएगा । विगत 22 फरवरी को हमने इस संचार नीति को अधिकारिक तौर से लागू किया है । आज इसकी एक प्रति मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अवलोकन हेतु उन्हें प्रस्तुत करना चाहूंगा।

केंद्र सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई को बहुत अहम महत्व देती है एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सुझावों का हम गहराई से अध्ययन करते हैं एवं आने वाली सभी अड़चनों को दूर करेंगे । कई राज्यों ने व्यक्तिगत शौचालयों की अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिस पर हम विचार कर रहे हैं एवं शीघ्र ही फैसला करेंगे ।

अंत में मैं यहां उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अच्छे कार्य करने पर बधाई देता हूं एवं महामहिम राष्ट्रपति जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि यहां उपस्थित होकर उन्होंने न सिर्फ इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है बल्कि असंख्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं को अनुप्राणित किया है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे ।

धन्यवाद

जय हिन्द